वित्तीय प्रावधानः इस कार्यक्रम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि (100 करोड़ रुपये) को संकलित कर कार्यान्वित किया जाएगा।

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा उचित प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थानों द्वारा तकनीकी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, यह कार्यक्रम जिला स्तर पर काम कर रहे विकास विभागों के कार्यक्रमों के साथ मिल कर लागू किया जाएगा। कृषि निवेशों का प्रयोग, कृषि में मशीनीकरण, नए तकनीकों को अपनाना और संस्थागत लिंकेज का विकास इन क्षेत्रों में अपेक्षानुसार नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत, वैज्ञानिक रूप से संस्तुत नयी तकनीकी को बढ़ावा देकर लोगों की जीविका सुधारने पर बल दिया जाएगा। फसल उत्पादन के साथ संबन्धित कार्य जैसे मछली उत्पादन एवं पशुपालन कार्यक्रम के अभिन्न अंग होंगे जिससे उत्पादकों को परिवार का पोषण सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी एवं इसको बाजार से ज़ोड़ कर जीविका सुरक्षा भी होगी।

इन क्षेत्रों में ऐसे बहुत से पौधे पारंपरिक रूप से उगाये जाते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं हैं परंतु औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इस तरह की विविधता भी समाप्ति की ओर है, इसलिए कार्यक्रम में ऐसे विशिष्ट फसलों एवं प्रजातियों को चिन्हित कर शोध एवं प्रसार कार्य में बढ़ावा दिया जाएगा तथा जैव विविधता को आजीविका के श्रोत के रूप में विकसित करने का प्रयास होगा।

जानकारी व संपर्क
उप महानिदेशक (कृषि प्रसार)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान भवन–I, पूसा, नई दिल्ली–110 012
फोनः 011–25843277 ई–मेलः aksicar@gmail.com

भाकृअनुप
ICAR

क्षमता

जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान प्रणाली एवं परिवार आधारित कृषि प्रबंधन

क्षमता

जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान प्रणाली एवं परिवार आधारित कृषि प्रबंधन

जनजातीय क्षेत्रों में विशिष्ट स्वदेशी संस्कृति है, परंतु भौगोलिक परिस्थिति के कारण इन क्षेत्रों का विकास एवं यहाँ के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत कम सुधार हुआ है। इन क्षेत्रों में स्थानीय कृषि ही आजीविका की प्रमुख धूरी है।

बुनियादी ढांचे की कमी, कठिन परिस्थिति, मौसम की अनियमितता एवं कृषि पर निर्भरता के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में आजीविका के नए श्रोत विकसित करने की जरूरत है। जनजातीय क्षेत्रों में कृषि से जुड़ी स्थानीय ज्ञान प्रणाली अच्छी तरह से विकसित है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण के प्रबंधन के मुद्दे को संबोधित करती है। इसके अलावा मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सांवा, आदि एवं पारंपरिक सब्जियाँ कम उत्पादकता के साथ जनजातीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। संतुलित आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि इन क्षेत्रों का विकास कृषि एवं परिवार आधारित मॉडल पर किया जाए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक पहल की है जिससे देश के 125 जिलों, जहां जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है, में कृषि विकास को गति प्रदान करने हेतु "क्षमता" (जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान प्रणाली एवं परिवार आधारित कृषि प्रबंधन) नामक कार्यक्रम कृषि उद्यम आधारित विकास की एक व्यापक रणनीति के साथ कार्यान्वित किया जाएगा ।

उद्देश्य

जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय ज्ञान प्रणाली का उपयोग करते हुये कृषि विकास

मुख्य गतिविधियां

- प्रचलित स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का संकलन एवं आंकलन
- पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली के विकास के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप
- जनजातीय क्षेत्रों के किसानों की आजीविका और पोषण सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का एकीकरण
- जनजातीय क्षेत्रों में पोषण समृद्ध फसलों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण
- मत्स्य पालन और पशुधन जैसी गतिविधियों पर प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण।

लक्ष्य: वर्ष 2019–20 तक 125 जिलों में, जहां जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है, कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कार्यक्रम का कार्यान्वयन

लक्ष्य: वर्ष 2019–20 तक 100 कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन

नारी कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी गतिविधियों का लक्ष्य निर्धारण चयनित जिलों में बेंचमार्क सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा। प्रस्तावित लक्ष्यों में निम्नलिखित का समावेश होगा:

- बेहतर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु पारिवारिक खेती करने हेतु कृषि महिलाओं के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन
- ग्रामीण स्कूलों को सम्मिलित करते हुये महिलाओं और युवाओं में स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन, पोषण कैलेंडर, पोषक थाली, आदि के प्रति रूचि और जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यकतानुसार कार्यक्रम का आयोजन
- पर्याप्त लघु और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर स्वस्थ आहार की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ''न्यूट्री–गार्डेन'' की स्थापना
- बच्चों एवं महिलाओं के विकास से जुड़े लोगों के लिए जागरूकता एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन।

इस कार्यक्रम से खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला विकसित करने एवं जागरूकता फैलाने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण महिलाओं के ज्ञान एवं कार्य करने के तरीके का आपस में आदान प्रदान होगा जिससे पोषण संवेदी कृषि को बढ़ावा देने में बल मिलेगा।

जानकारी व संपर्क
उप महानिदेशक (कृषि प्रसार)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान भवन–I, पूसा, नई दिल्ली–110 012
फोनः 011–25843277 ई–मेलः aksicar@gmail.com

भाकृअनुप
ICAR

नारी

पोषण-संवेदी कृषि संसाधन एवं नवोन्मेषण

नारी

पोषण-संवेदी कृषि संसाधन एवं नवोन्मेषण

भारत में कृषि क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक विकास में बहुमुखी योगदान दिया है, परंतु पोषण सुरक्षा के ऊपर भी बल दिया जाना आवश्यक है। देश में स्थानीय फलों, सब्जियों एवं पोषणयुक्त खाद्यान फसलों की बहुतायत उपलब्धता है जिसमें विटामिन एवं खनिज पदार्थों की उपलब्धता प्रचुर मात्र में है। इन फसलों को परिवार के गृहवाटिका में महिलाओं की देख–रेख में उगा कर वृद्ध, युवा एवं बच्चों को आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य पूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। फसलों, पशुधन, मछली और दूध की बढ़ी हुई पैदावार तथा खाद्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि ने देश को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। परंतु, कुपोषित एवं कम वजन वाले बच्चों की अधिक संख्या तथा उनके पोषण संबंधी मुद्दों को हल करने हेतु तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ पोषण सुरक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए "पोषण अंतर" को कम करना आवश्यक है। एक स्वस्थ देश के लिए सभी क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए जो स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में एक प्रमुख कारक है। इसके लिए कृषि को पोषण से जोड़ने की अवधारणा पर कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही पोषण अंतर को कम करने हेतु स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़े। समस्त परिवार के पोषण का घर की महिलाओं द्वारा ध्यान रखा जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के संयोजन से लेकर किचन गार्डेन में विभिन्न प्रकार के पोषणयुक्त फलों तथा सब्जियों का उगाना भी शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा "नारी" (पोषण–संवेदी कृषि संसाधन एवं नवोन्मेषण) नामक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यह कार्यक्रम महिला केन्द्रित है तथा महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए संचालित किया जाना है। कार्यक्रम के संचालन में कृषि विज्ञान केन्द्रों में नियुक्त विषय वस्तु विशेषज्ञों (गृह विज्ञान) को प्रमुख भूमिका निभाना है और महिला समूहों के माध्यम से इसको संचालित करना है।

उद्देश्य

- कृषि को पोषण से जोड़ना ताकि पोषण संवेदनशील कृषि को बढ़ावा मिले
- कृषि महिलाओं और ग्रामीण युवाओं में पोषण संवेदनशील कृषि के बारे में जागरूकता पैदा करना
- पोषण बागवानी पर जागरूकता पैदा करना।

मुख्य गतिविधियां

- महिलाओं और युवकों को पोषण युक्त फसल उत्पादन के प्रति जागरूक करना
- स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन
- पोषण युक्त फसलों व प्रजातियों पर प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण
- प्रदर्शन के माध्यम से पोषण – संवेदनशील कृषि को बढ़ावा देना
- प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास।

कृषि विज्ञान केन्द्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा संचालित "संपदा योजना" तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के अंतर्गत परियोजना प्रस्तुत कर वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे। जिस विषय पर प्रशिक्षण द्वारा युवकों को दक्ष किया जाना है उससे संबन्धित तकनीक युक्त इकाई की स्थापना कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रांगण में की जाएगी तथा उत्साही युवकों का चयन कर उन्हें व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे अपने गाँव के स्तर पर अपनी इकाई स्थापित कर सकें।

लक्ष्य: वर्ष 2019–20 तक 100 वाटिका केन्द्रों की स्थापना।

जानकारी व संपर्क
उप महानिदेशक (कृषि प्रसार)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान भवन–I, पूसा, नई दिल्ली–110 012
फोन: 011–25843277 ई–मेल: aksicar@gmail.com

भाकृअनुप
ICAR

वाटिका

कृषि में मूल्यसंवर्धन और टेक्नोलौजी इन्क्यूबेशन सेंटर

वाटिका

कृषि में मूल्यसंवर्धन और टेक्नोलौजी इन्क्यूबेशन सेंटर

रिकार्ड उत्पादन के बावजूद कटाई उपरांत प्रबंधन के अभाव में उत्पादों की बर्वादी के कारण किसानों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान होता है। उचित प्रबंधन के अभाव में कटाई उपरांत फसल और सब्ज़ियों में औसतन 10 से 30 प्रतिशत और अनाज में औसतन 8–10 प्रतिशत का नुकसान होता है। अगस्त 2016 के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रमुख कृषि उपज का नुकसान 92,651 करोड़ रुपये के बराबर है। कृषि उत्पादों का उचित प्रसंस्करण न केवल नुकसान को रोकता है और उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि इससे उत्पादों की बिकने की क्षमता भी बढ़ती है जो बदले में उत्पादकों को बढ़ी हुई आय प्रदान करती है। वर्तमान परिदृश्य में एकीकृत प्रयास करने की जरूरत है जिसमें सिद्ध प्रक्षेत्र तकनीकी एवं कटाई उपरांत प्रयोग किए जाने वाले तकनीकी को समाविष्ट करते हुये ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जाए जिसमें समुदाय आधारित संगठन एवं किसान उत्पादक संगठन प्रमुख भूमिका निभा सकें। ऐसे प्रावधान कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि विभागों के द्वारा बनाए जाने की जरूरत है।

कटाई उपरांत उत्पादों की बर्वादी से किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान तथा कृषि उत्पादों के उचित प्रसंस्करण से होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा "**वाटिका**" (**कृषि में मूल्यसंवर्धन और टेक्नोलौजी इन्क्यूबेशन सेंटर**) नामक पहल की शुरुआत की जा रही है। **वाटिका** का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक रूप से टिकाऊ मॉडल के माध्यम से कटाई उपरांत प्रबंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है ताकि उत्पादों की बर्वादी को कम करके किसानों को आर्थिक हानि से बचाया जा सके तथा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा कर कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सके।

उद्देश्य

- कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त कटाई उपरांत प्रबंधन प्रौद्योगिकी का प्रसार
- किसानों, युवकों एवं किसान उत्पादक संगठनों को कटाई उपरांत प्रबंधन प्रौद्योगिकी पर लम्बी अवधि का कौशल परक प्रशिक्षण
- युवकों/किसानों द्वारा इकाई स्थापित करने हेतु तकनीकी सहयोग एवं नियमित सलाह।

कार्यान्वयन के मॉडल

कृषि विज्ञान केन्द्रों के परिसर में वाटिका की स्थापना कर किसानों, युवकों तथा किसान उत्पादक संगठनों के सदस्यों के कौशल विकास हेतु इनका संचालन किया जाएगा। प्रशिक्षित उद्यमियों को अपनी इकाई स्थापित करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र उनको वित्तीय संस्थाओं से जोड़ेंगे। साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र उनको लंबे समय तक तकनीकी सलाह देते रहेंगे जिससे वे इकाई स्थापित करने के शुरुआती दौर में आने वाली कठिनाइयों से निजात पा सकें।